



BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India



कृषि संबद्ध क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता

“विकास, नवाचार और किसान सशक्तिकरण का एक दशक”

15 अगस्त, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 अगस्त, 2025 को स्वतंत्रता दिवस समारोह पर उद्बोधन:

- आज भारत दूध, दाल, जूट जैसे उत्पादन में नंबर वन है दुनिया में। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर मेरे मछुआरे भाई बहनों के ताकत देखिए, फिश प्रोड्यूसर में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। आज भारत चावल, गेहूं, फल और सब्जी के उत्पादन में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है।
- आपको खुशी होगी मेरे देश के किसान जो पैदाई देते हैं आज वह उत्पादन दुनिया के बाजार में पहुंच रहा है। 4 लाख करोड़ रुपया एगो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। ये मेरे देश के किसानों ने हमें ताकत दिखाई है। हम छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, देश के विकास खाने की योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे हैं।
- पीएम किसान सम्मान निधि हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सिंचाई की योजनाएं हो, क्वालिटीज सीड्स हो, फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो, हर क्षेत्र में आज और किसान को एक भरोसा हो गया है फसल बीमा का।
- भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बनके खड़ा है।
- भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा।

परिचय

कृषि में, पशुपालन (डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी और भेड़ पालन, सूअर पालन), मत्स्य पालन और जलीय कृषि (अंतर्देशीय और समुद्री) और बागवानी (फल, सब्जियां, फूल, मसाले, औषधीय पौधे) जैसे संबद्ध क्षेत्र फसल की खेती से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और ग्रामीण आय में विविधता लाने, जोखिम कम करने और साल भर आजीविका सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूमि, जल और फसल अवशेषों जैसे साझा संसाधनों का उपयोग करके, ये गतिविधियां फसल उत्पादन को पूरक बनाती हैं, कृषि अर्थव्यवस्था में मूल्य जोड़ती हैं और लाखों ग्रामीण परिवारों का समर्थन करती हैं। मानसून के उतार-चढ़ाव के प्रति कम संवेदनशील होने के साथ, ये लचीलेपन और ग्रामीण विकास के प्रमुख चालक हैं, और **आत्मनिर्भर भारत** विजन के तहत, आयात निर्भरता को कम करने, ग्रामीण आय को बढ़ावा देने, मूल्य संवर्धन को बढ़ाने और सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए इन गैर-फसल गतिविधियों को मजबूत और आधुनिक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र -

- जुलाई 2025 तक, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग **49.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंच गया, जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात लगभग 20.4% है।
- प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात हिस्सेदारी 2014-15 में 13.7% से बढ़कर 2024-25 में 20.4% हो गई है।

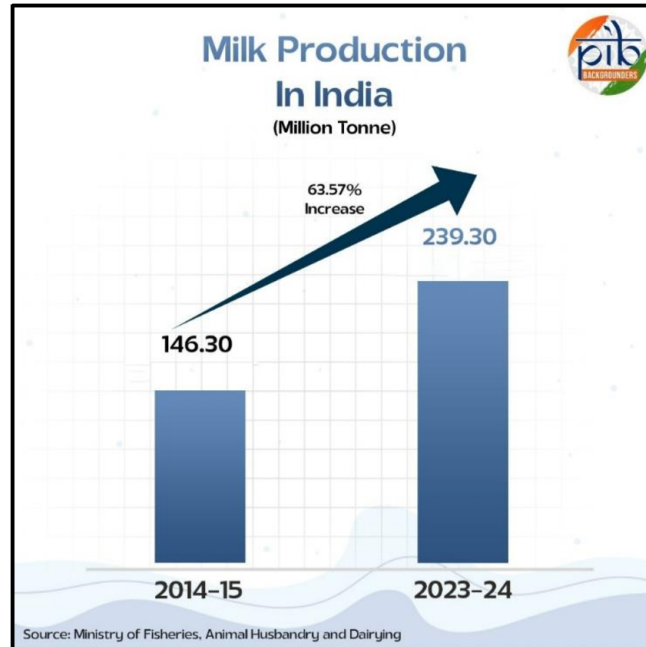
नीली क्रांति-

- मछली उत्पादन 2013-14 में **96 लाख टन** से **104% बढ़कर** 2024-25 में **195 लाख टन** हो गया है।
- इसी अवधि में अंतर्देशीय मत्स्य पालन में **142% की वृद्धि हुई है**, जो **61 लाख टन से बढ़कर 147.37 लाख टन** हो गया है।
- **केंद्रीय बजट 2025-26 में**, मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 2,703.67 करोड़ रुपये (**2024-25 के बजट से 3.3% की वृद्धि**) के समर्थन के साथ अब तक का सबसे अधिक कुल वार्षिक बजटीय समर्थन 2025-26 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है।

डेयरी क्षेत्र -

- भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में **प्रथम स्थान** पर है, जो वैश्विक उत्पादन में 25% का योगदान देता है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.7% रही है, जो वैश्विक औसत 2% से काफी अधिक है।
- देश में दुग्ध उत्पादन पिछले 10 वर्षों में **63.57% बढ़ा है**, जो 2014-15 में 146.30 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में 239.30 मिलियन टन हो गया है।
- भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 48% बढ़कर 2023-24 में 471 ग्राम/व्यक्ति/दिन हो गई है, जबकि वैश्विक औसत 322 ग्राम/व्यक्ति/दिन है।
- कुल दुग्ध उत्पादन में **गायों और भैंसों का योगदान क्रमशः 53.12% और 43.62% है।**
- डेयरी क्षेत्र में **8 करोड़ से अधिक किसान** कार्यरत हैं।
- संशोधित एनपीडीडी योजना के तहत, पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएचडी) ने 2025-26 के दौरान देश भर में 21,902 नई डेयरी सहकारी समितियों के संगठन के लिए राज्यवार लक्ष्यों को मंजूरी दी है।

- कुल स्वीकृत वित्तीय परिव्यय: ₹407.37 करोड़।
- भारत सरकार का हिस्सा: ₹211.90 करोड़।
- कार्यान्वयन संगठनों का हिस्सा: ₹195.47 करोड़।
- राज्यों से मिली रिपोर्टों के अनुसार, 2025-26 तक अब तक लगभग 1,804 दुग्ध (डेयरी) सहकारी समितियां गठित की जा चुकी हैं।
- इन सहकारी समितियों ने लगभग 37,793 नए दुग्ध उत्पादकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं।



- 19 मार्च, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 के लिए ₹2,790 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) और ₹3,400 करोड़ के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) को मंजूरी दी। इन योजनाओं का उद्देश्य दूध की खरीद, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना, स्वदेशी मवेशी प्रजनन को बढ़ावा देना, डेयरी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और ग्रामीण आय और विकास को बढ़ाना है।

मीठी क्रांति -

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)

आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में 2020 में शुरू किया गया, जिसका 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए कुल परिव्यय ₹500 करोड़ है। इस योजना को ₹370 करोड़ के शेष बजट के साथ, 2023-24 से 2025-26 तक, तीन और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

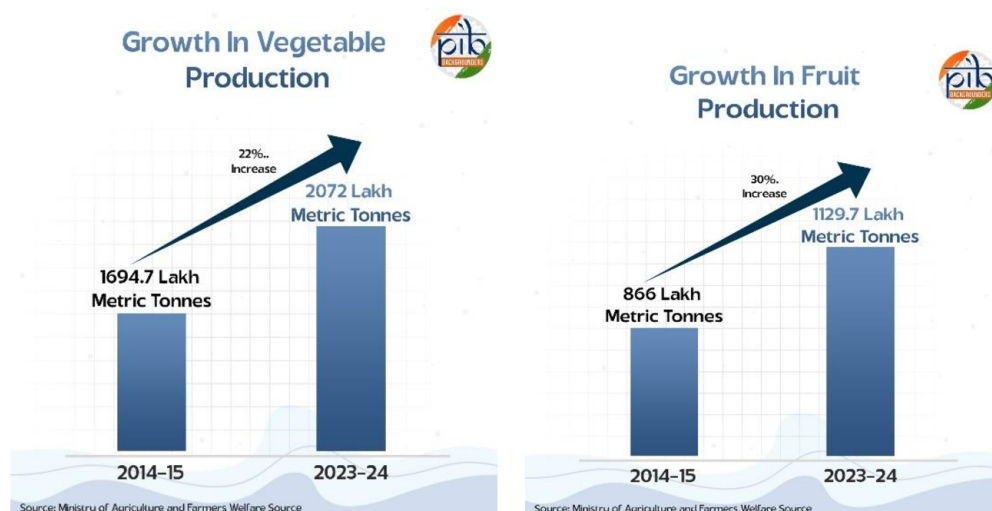
एनबीएचएम की प्रमुख उपलब्धियां:

- भारत ने 2022-23 में 1.42 लाख मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया और 79,929 मीट्रिक टन शहद का निर्यात किया।

- सशक्तिकरण के लिए 167 महिला स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों को समर्थन दिया गया।
- मधुमक्खी पालन केंद्रों की बढ़ती मांग को देखते हुए, 31.12.2025 तक 2,000 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य लागू किया गया है।
- 6 विश्वस्तरीय और 47 लघु शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं, साथ ही 6 रोग प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।
- 8 कस्टम हायरिंग केंद्र, 26 शहद प्रसंस्करण इकाइयां और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है।
- ऑनलाइन पंजीकरण और ट्रेसेबिलिटी के लिए मधुक्रांति पोर्टल शुरू किया गया - 14,800 से अधिक मधुमक्खी पालक और 22.39 लाख कॉलोनियां पंजीकृत हुईं।
- ट्राइफेड, नेफेड और एनडीडीबी के तहत मधुमक्खी पालकों के लिए 100 में से 7 एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) बनाए गए।

बागवानी

पिछले एक दशक में बागवानी क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। फलों का उत्पादन 2014-15 के 866 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 1129.7 लाख मीट्रिक टन हो गया, जो लगभग 30% की वृद्धि दर्शाता है। इसी अवधि में सब्जियों का उत्पादन भी 1694.7 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2072 लाख मीट्रिक टन हो गया, जो 22% की वृद्धि दर्शाता है।



इथेनॉल खरीद

सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के माध्यम से पेट्रोल के साथ इथेनॉल के मिश्रण को प्रोत्साहित कर रही है, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति करती हैं। यह पहल न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देती है, बल्कि इथेनॉल की निरंतर मांग पैदा करके गन्ना किसानों को एक स्थिर आय स्रोत भी प्रदान करती है। इथेनॉल की कीमतों में वृद्धि और जीएसटी व परिवहन शुल्क का अलग-अलग भुगतान किसानों की आय को और मजबूत करता है। चालू इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2024-25 में, ओएमसी ने 31 जुलाई 2025 तक 19.05% का औसत इथेनॉल मिश्रण स्तर हासिल कर लिया है। अकेले जुलाई 2025 में, मिश्रण स्तर 19.93% तक पहुंच गया।

पिछले 11 वर्षों में, इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2014-15 से ईएसवाई 2024-25 और जुलाई 2025 तक, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से ₹1,44,087 करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। इसने लगभग 245 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का विकल्प प्रदान किया है, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है, और सीओ2 उत्सर्जन में लगभग 736 लाख मीट्रिक टन की कमी की है -

जो 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर का पर्यावरणीय लाभ है। 20% मिश्रण पर, इस वर्ष अकेले किसानों को ₹40,000 करोड़ का भुगतान और लगभग ₹43,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा बचत होने की उम्मीद है।

मुख्य उपलब्धियां

- इथेनॉल की खरीद 2013-14 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 2023-24 में 441 करोड़ लीटर हो गई।
- चीनी सीजन 2023-24 में गन्ना किसानों को 1,11,703 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
- किसानों के लिए बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करने हेतु सी-हैवी मोलासेस (सीएचएम) इथेनॉल की कीमत में 3% की वृद्धि।
- अलग जीएसटी और परिवहन शुल्क से किसानों की आय में सीधा लाभ होगा।

यह कार्यक्रम किसानों की आय दोगुनी करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)

पीएम-कुसुम का उद्देश्य कृषि में डीजल के उपयोग को कम करना और किसानों की आय को बढ़ावा देना है। यह योजना एकल सौर पंप स्थापित करने और मौजूदा पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए 30-50% केंद्रीय सब्सिडी प्रदान करती है। किसान बंजर भूमि पर 2 मेगावाट तक के सौर संयंत्र भी स्थापित कर सकते हैं और डिस्कॉम को बिजली बेच सकते हैं। यह योजना स्वच्छ ऊर्जा और आय सृजन को बढ़ावा देती है और राज्य सरकार के विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

पीएम-कुसुम योजना का लक्ष्य मार्च 2026 तक 34,800 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ना है, जिसके लिए कुल 34,422 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए सेवा शुल्क भी शामिल है।

पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत उपलब्धियां

- किसानों के लिए सौर पंपों की संख्या में 92 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।
- इस योजना के अंतर्गत 49 लाख कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा।
- स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा, डीजल पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय में वृद्धि।

संदर्भ

PIB

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2150877>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2152462>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2155110>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2155558>

<https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NotelId=154580&ModuleId=3>

Lok Sabha

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU3905_0Fned9.pdf?source=pqals

पीके / केसी/ एमपी